1988 में तत्कालीन सीएम एनडी तिवारी ने किया था गीडा का ऐलान, कुछ दिन बाद चीनी मिल बंद हुई, औद्योगिक विकास भी हो गया ठप

धुरियापार से हुई थी गीडा की घोषणा अब औद्योगिक विकास का केन्द्र

स्थापना दिवस

209 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास होगा

1068 करोड़ निवेश करने वाले उद्यमियों को मिलेगा आवंटन पत्र

- धुरियापार और आसपास के 17 गांवों में अधिग्रहीत की जानी है 5500 एकड़ जमीन
- 500 एकड़ जमीन का हो चुका है अधिग्रहण, अदाणी व जेके सीमेंट की यूनिट लगेगी

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकारण (गीडा) के लिए 11 दिसम्बर, 1988 की तारीख बेहद अहम है। इसी दिन धुरियापार चीनी मिल का शुभारंभ करने पहुंचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने गीडा की स्थापना का ऐलान किया था। आगे चलकर धुरियापार चीनी मिल बंद हो गई, और यहां औद्योगिक विकास भी ठप हो गया। इसके करीब 36 साल बाद अब धुरियापार औद्योगिक विकास का केन्द्र बन गया है। यहां बायो गैस प्लांट चालू हो चुका है तो वहीं अदाणी और जेके सीमेंट की यूनिटें स्थापित होने जा रही हैं।

प्रदेश की योगी सरकार में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के साथ रेलवे कनेक्टिविटी के चलते धुरियापार क्षेत्र में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है। धुरियापार और आसपास के 17 गांवों में 5500 एकड़ जमीन अधिग्रहीत होनी है, जिसमें से 500 एकड़ से अधिक जमीन पर औद्योगिक विकास वजूद में आता दिखने लगा है। धुरियापार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जो गांव अधिसूचित हैं, उनमें बाथ बुजुर्ग, बाथ खुर्द, भिसमपट्टी, चाडी, धोरहरा, दिघरूआ, दोदापार, दुबरीपुरा, गजपुर, गौरखास, हरपुर, काशतकाशी नायक, मठदुर्वाशा, नारायण खुर्द, परसा बुजुर्ग, पुरादयाल और सकरदेइया शामिल हैं।

पहले चरण में सकरदेईया, हरपुर और काशतकाशी नायक गांवों में करीब 1600 एकड़ भूमि अर्जित होनी है। गीडा इसमें से 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर चुका है। धुरियापार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मास्टर प्लान फाइनल है, बस इसे शासन से अनुमोदन का इंतजार है। मास्टर प्लान के मुताबिक कुल क्षेत्रफल में 32.04 प्रतिशत क्षेत्र औद्योगिक, 19.39 प्रतिशत आवासीय, 6.51 प्रतिशत पीएसपी, 4.21 प्रतिशत व्यावसायिक, 15.70 प्रतिशत हरित-खुला क्षेत्र, 2.32 प्रतिशत मिश्रित, 4.17 प्रतिशत ट्रांसपोर्ट सुविधाओं के लिए प्रस्तावित है।

गुरुवार को डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीना ने गीडा की सीईओ अनुज मलिक के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

चालू है इंडियन ऑयल का कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट

धुरियापार में बनने के बाद से ही बंद पड़ी चीनी मिल के कुछ हिस्से में इंडियन ऑयल की तरफ से कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाया जा चुका है। सीईओ का कहना है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़े होने के साथ ही सहजनवा से दोहरीघाट तक प्रस्तावित नई रेल लाइन परियोजना भी यहां से गुजर रही है। ऐसे में यहां बड़े उद्योगों के लिए पृथक से रेलवे साइडिंग दिए जाने की भी व्यवस्था होगी।

ओडीओपी के उत्पाद होंगे आकर्षण का केंद्र

प्रदर्शनी स्थल पर 51 स्टॉल ओडीओपी व अन्य ऐसे उत्पादों के लिए रखे गए हैं। ओडीओपी स्टॉल पर गोरखपुर के टेराकोटा, रेडिमेड गारमेंटस, कुशीनगर के केला रेशा उत्पाद, महराजगंज के फर्नीचर आदि के अलावा अयोध्या का गुड़ रखा जाएगा। वहीं, बलिया की बिंदी, आजमगढ़ का ब्लैक पाटरी, आगरा का पेठा, कानपुर का लेदर शूज, तखनऊ की कढ़ाई, बनारसी सिल्क साड़ी के लिए भी स्थान निर्धारित किया जा रहा है।

800 एकड़ में विकसित हो रहा औद्योगिक गलियारा

गोरखपुर। गीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 800 एकड़ में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। यहीं पर गीडा की तरफ से 88 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां प्लास्टिक उद्योग की 92 इकाइयों के लिये स्थान एवं समस्त आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे लगभग 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। प्लास्टिक पार्क की यूनिट्स को परियोजना स्थल पर ही गेल की तरफ से कच्चा माल सुलभ होगा। प्लास्टिक पार्क में गीडा द्वारा परियोजना स्थल पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंगएंड टेक्नोलॉजी (सीपेट) के सेंटर के लिए भी 5 एकड़ निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इससे कुशल कारीगरों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ उनके द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

> धुरियापार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए निवेश प्रस्ताव आने शुरू हो गए हैं। अदाणी समूह और जेके ग्रुप ने इस कॉरिडोर में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए क्रमशः 65 और 50 एकड़ जमीन की मांग की है। इसके अलावा कई अन्य औद्योगिक समूह यहां निवेश में रुचि दिखा रहे हैं।
>
> – अनुज मलिक, सीईओ, गीडा

पहली प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट को आवंटन पत्र देंगे सीएम

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तर भारत के पहली प्लास्टिक रिसाइकिलिंग यूनिट लगाने वाले निवेशक को भूखंड का आवंटन पत्र देंगे। गीडा के स्थापना दिवस पर सीएम कुल पांच निवेशकों को आवंटन पत्र देंगे। दो दिवसीय प्रदर्शनी के शुभारंभ के साथ ही सीएम उत्पादों का अवकोलन भी करेंगे।

गीडा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सीएम योगी गीडा में करीब एक घंटे रहेंगे। सीएम दोपहर बाद गीडा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के हाथों कोका कोला के बाटलिंग प्लांट का काम देखने वाली एसएलएमजी ग्रुप, एपीएल अपोलो स्टील पाइप, मार्डन पैकेजिंग समेत पांच निवेशकों को आवंटन पत्र देंगे। एसएलएमजी ग्रुप प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का यूनिट भी लगाएगी। कंपनी को गीडा ने 16 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। स्थापना दिवस पर औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई, निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' और औद्योगिक आयुक्त मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे।

गीडा में निवेश को 1990 में बनी थी 791 उद्यमियों की सूची

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। गीडा को लेकर चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से संघर्ष अस्सी के दशक में शुरू हो गया था। उद्यमियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संघर्ष 30 नवम्बर, 1989 में जमीन पर आता दिखा जब प्रदेश सरकार ने गीडा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया।

चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल बताते हैं कि फरवरी, 1989 में यूपी के बजट में गोरखपुर में सहजनवां और जौनपुर में सथरिया को औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने का ऐलान किया गया था। इसके पहले केन्द्र सरकार ने 10 जनवरी, 1989 को देश के 38 ग्रोथ सेंटर में गोरखपुर के सहजनवां को शामिल किया था। पहली बार इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया था। पुराने उद्यमी बताते हैं कि गीडा की स्थापना की घोषणा तो हुई लेकिन इसके विकास को लेकर प्रभावी कोशिशें नहीं हो रही थीं।

5 करोड़ का चेक लेकर पहुंचे थे कल्याण सिंह

पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल बताते हैं कि गीडा की स्थापना की घोषणा तो हो गई लेकिन बजट के अभाव में जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई कवायद नहीं हो रही थी। संघ के एक सक्रिय पदाधिकारी से मुलाकात के बाद वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह गीडा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये का चेक लेकर आए थे। जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की कवायद शुरू हुई।